(b) whether Government are aware that investment for every MW calls for equal or more investment in Transmission and Distribution System; and

(c) if so, what would be the source of funding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The targets for the Ninth Five Year Plan are yet to be finalised. The cost per MW for power projects is project specific as it depends on various factors. The requirement of funds could be indicated only on finalisation of the Ninth Plan.

(b) and (c) Matching investment for transmission and distribution would also be considered while finalising the Plan. All possible sources of finances, including private investment and external assistance, would need to be explored.

Development of North Eastern Region and Coastal Areas

2881. SHRI V. NARAYANASAMY. Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have initiated any special programmes for economic development of the North Eastern Region, including Assam, and the Coastal areas, particularly Pondicherry;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is any move to repeal IMDT Act, 1983, to stop influx of foreigners into our country; and

(d) if so, the measures being taken to protect genuine Indian citizens from harassment?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) and (b) Government of India have recently announced new initiatives for the North-Eastern (NE) region which inter-alia include the following:—

1. A high-level Commission has been set up to examine the gaps in important sectors as well as the backlog in Basic Minimum Services. Recommendations of this Commission would be considered for formulation of specific programmes and funding arrangements for the development of NE States in the Ninth Five Year Plan.
2. A high-level expert committee has been set up to examine all aspects of problem pertaining to educated unemployed and to suggest specific steps to promote their employment.
3. All central ministries/departments will earmark at least 10% of their budget for specific programmes in the NE States.
4. The Border Area Development Programme and Border Road Programme will be extended to some more areas on the Indo Myanmar border.

As regards coastal areas (including Pondicherry) various development programmes are being implemented in these areas but no special programme has been initiated by Central Government specifically for them.

(c) and (d) Proposals have been received from various quarters for the repeal of the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983. No decision in the matter has yet been taken.

पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा "इमरजेन्सी रिस्टोरेशन सिस्टम" खरीदा जाना

2882. श्री राधवजी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पावर ग्रिड कारपोरेशन ने हाल में किससे, कब और कितनी कीमत का "इमरजेन्सी रिस्टोरेशन सिस्टम" खरीदा है;

(ख) आमंत्रित की गई निविदाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त सिस्टम को विक्रेता कम्पनी द्वारा पूर्व प्रस्तावित कीमत से अधिक कीमत पर खरीदा गया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री: (डा॰ एस॰ वेनुगोपालचारी: (क) और (ख) इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम (ईआरएस) नौ टावर पैकेजों में एकमात्र ऐसा घटक है जिसके लिए पावरग्रिड कारपोरेशन इंडिया लि॰ (पावरग्रिड) द्वारा विंध्याचल-धूले, नाथपा झाकरी तथा किशनपुर-मोगा के संबंध में21.1.1994 से 11.4.1994 तक, नाथपा झाकरी के संबंध में 7.2. 1994 से 25.4.1994 तक तथा विंध्याचल-धूले के संबंध में 15.12.1993 से 3.3.1994 तक बोली दस्तावेजों को, जिसमें संविदा की दशाएं और तकनीकी विशिष्टताएं समाविष्ट हैं, विक्रय हेतु रखा गया था। तीनों पारेषण प्रणालियों के लिए बोलियां क्रमश: 3. 3.1994, 17.5.1994 तथा 6.5.1994 को खोली गई थी। समग्र पैकेज के लिए उद्धृत की गई कुल कीमत के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन/तुलना की गई थी और इस संबंध में प्रत्येक वस्तु की दरों पर विचार नहीं किया गया था। सभी पैकेज के लिए न्यूनतम मूल्यांकन बोलीदाताओं को ठेका प्रदान किए गए थे।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मध्य प्रदेश में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु कैपेसिटर

2883. **श्री दिलीप सिंह जुदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी क्षमता के कितने कैपेसिटर स्थापित किए गए;

(ख) वास्तव में कितने कैपेसिटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) ये कैपेसिटर किन-किन स्थानों पर लगाए गए थे और किन-किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किए जाने हेतु प्रस्ताव किए जाने के बावजूद स्थापित नहीं किया जा सका तथा इसके क्या कारण थे; और

(घ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से इस संबंध में मांगी गई सहायता और वास्तव में प्रदान की गई सहायता के संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेनुगोपालाचारी): (क) से (ग) सूचना विवरण (क) से (ग) में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(घ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी है।

विवरण-क

वर्ष 1995- 96 के दौरान कैपेसिटर स्थापित करने के लक्ष्य तथा अधिष्ठापित कैपेसिटरों की संख्या (वर्ष 1995-96 के दौरान कैपेसिटरों सहित)

क्र.सं.	वोल्टता दर	वर्ष 1995-96 के दौरान कैपेसिटर स्थापना संबंधी लक्ष्य, सं. (क्षमता)	1995-96 के दौरान स्थापित कैपेसिटर सं. (क्षमता)
1.	33 के.वी.	18 (270 एमवीएआर)	20 (190 एमवीएआर)
2.	11 के.वी.	50 (50 एमवीएआर)	48 (52.2 एमवीएआर)